[2009] एस. सी. आर. 574

सुबोध कुमार यादव

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 1234)

15 जुलाई, 2009

**[आर. वी. रवींद्रन और जे. एम. पांचाल, न्यायमूर्तिगण]**

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 439-जमानत - रद्द करना-प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना-सत्र न्यायाधीश दंडाधिकारी द्वारा आवेदक को दी गई जमानत को रद्द कर दी उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा - मानाः दंडाधिकारी ने दं०सं०प्र० की धारी 437 के तहत अपने विवेक का प्रयोग किया। अप्रत्यक्ष उद्देश्य और मनमाने तरीके से-उन्होंने अप्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखा जिनका शिकायत में कभी उल्लेख नहीं किया गया था-सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में दंडाधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने और यह मानने में उचित ठहराया कि उक्त आदेश न्यायिक के अलावा अन्य विचारों के लिए पारित किया गया था।*

**उत्तरदाता सं. 2 ने भा०दं०सं० की धारा 498 के तहत अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ के तहत शिकायत दर्ज की। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत के लिए आवेदन दायर किया। दंडाधिकारी ने जमानत दे दी। हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील।**

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित: 1. जमानत के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार करते समय जमानत अस्वीकृति के लिए प्रासंगिक कारकों की तुलना में पहले से दी गई जमानत पर विचार, जमानत रद्द करने के लिए, जमानत पर रिहाई के बाद की आचरण तथा परिस्थितियों पर विचार प्रासंगिक होगा। इसका उद्देश्य किसी उच्च न्यायालय की उचित परिस्थितियों में जमानत रद्द करने की शक्ति को मामलों अन्य आधारों पर सीमित करना नहीं है यदि उच्च न्यायालय पाता है कि जमानत देने वाली अदालत ने अप्रासंगिक सामग्री पर काम किया हे या यदि विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है या जमानत देने के लिए किसी वैधानिक प्रतिबंध पर ध्यान नहीं दिया गया है, या यदि स्पष्ट रूप से अनुचितता है, तो जमानत रद्द करने का आदेश वास्तव में दिया जा सकता है। [पैरा 9] [581-बी-डी]

2.1 अपीलार्थी ने स्वयं और अन्य लोगों ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए पुनरीक्षण दायर करके सत्र न्यायालय का रुख किया था और इसलिए, सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से अभिलेख मांगा था। 19 अक्टूबर, 2002 को अपीलार्थी ने अचानक न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का फैसला किया था और एक जमानत याचिका दायर की। दंडाधिकारी ने पाया कि मामले का अभिलेख पुनरीक्षण के संदर्भ में सत्र न्यायालय में पड़ा हुआ था, जिसे अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया था। दंडाधिकारी ने इंतजार करना उचित नहीं समझा। और एक न्यायिक आदेश पारित करके एक उच्च न्यायालय में लंबित अभिलेख के लिए कहा गया। दंडाधिकारी द्वारा पारित न्यायिक आदेश को देखते हुए, सत्र न्यायालय की रजिस्ट्री ने मामले का अभिलेख तुरंत न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को भेज दिया। इसके बाद, दंडाधिकारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करने के लिए आगे बढ़े। अभिलेख को मंगाने के आदेश में, दंडाधिकारी द्वारा यह कहीं भी संकेत नहीं दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत

आवेदन पर उसी दिन-19 अक्टूबर, 2002 को सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता के वकील को बिल्कुल भी नोटिस पर नहीं रखा गया था और इसलिए, उस समय उपस्थित नहीं रह सके जब जमानत याचिका सुनवाई के लिए ली गई थी। दंडाधिकारी ने अपीलार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया। बेशक वे दस्तावेज़ संज्ञान लेने के समय के बाद के थे। उन दस्तावेजों पर विचार करने के बाद दंडाधिकारी ने अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया। दंडाधिकारी द्वारा प्रदर्शित अनुचित जल्दबाजी के साथ-साथ जमानत पर सुनवाई करने का उनका निर्णय उसी दिन शिकायतकर्ता के वकील को सुने बिना आवेदन पर सुनवाई का निर्णय लेना भी गलत है न्यायाधीश को दंडाधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर कर दिया। तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर, सत्र न्यायाधीश को दंडाधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने और यह अभिनिर्धारित करने में उचित ठहराया गया कि जमानत देने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक के अलावा अन्य विचारों के लिए पारित किया गया था। तथ्य की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई। [पैरा 11] [581-एफ-एच; 582-ए-एफ]

2.2. सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि दंडाधिकारी ने दं०प्र०सं० की धारा 437 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया था। दंडाधिकारी जाहिरा तौर पर अपीलार्थी को जमानत देने पर आमादा था और इसलिए, उसने न केवल उसी दिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया, बल्कि उच्च न्यायालय से अभिलेख भी मांगा और शिकायतकर्ता के वकील को सुने बिना अपीलार्थी को जमानत दे दी। चूंकि न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से तथा परोक्ष उद्देश्यों से न्यायिक विवेक का प्रयोग किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता को जमानत देने के आदेश को रद्द करने में सत्र न्यायालय का औचित्य था। दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश उसके निहित विवेक के मनमाने प्रयोग का परिणाम था। इसके अलावा दंडाधिकारी ने पूरी तरह से अप्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार किया था जिनका

**शिकायत में कभी भी उल्लेख नहीं किया गया था। उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए दंडाधिकारी ने अपीलार्थी को किसी भी तरह जमानत पर रिहा करने के लिए अपनी उत्सुकता प्रदर्शित की। तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के उस जमानत को रद्द करने के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटियां नहीं की, जिसे न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को मनमाने ढंग से दिया गया था, तथा मजिस्ट्रेट, इस प्रकार, अपील खारिज होने योग्य है। [पैरा 12] [583-बी-ई]**

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी **(2005) 8 एस. सी. सी. 21;** गजानंद अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य **2006 (9) स्केल 378;** रिज़वान अकबर हुसैन सैयद बनाम महमूद हुसैन **2007 (10) एस. सी. सी. 368** पर भरोसा किया गया।

**मामला कानून संदर्भः**

| | | |
|---|---|---|
| (2005) 8 एससीसी 21 | पर भरोसा किया | पैरा-9 |
| 2006 (9) स्केल 378 | पर भरोसा किया | पैरा-9 |
| 2001 (10) एससीसी 368 | पर भरोसा किया | पैरा-9 |

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2009 की आपराधिक अपील सं. 1234।

आपराधिक विविध सं. 2790/2004, मामले में पटना में उच्च न्यायालय के न्याधिकरण के 2.5.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए अनुकुल राज और आर. नेदुमारन।

उत्तरदाताओं की ओर से मनीष कुमार और गोपाल सिंह।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था।

**जे. एम. पांचाल, जे.**

अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2 मई 2007 तारीख जिसके द्वारा पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण सं. 2790 ऑफ 2004 में दिया गया फैसले के खिलाफ की गई है, जिसके द्वारा 8 जनवरी, 2004 को विद्वत सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण सं. 13 ऑफ 2003 में पारित आदेश, जिसमें विद्वत एस. डी. जे. एम., पूर्णिया द्वारा अपीलार्थी को दी गई जमानत रद्द की गई थी, 19 अक्टूबर, 2002 के आदेश द्वारा, सी. ए. नं. 1098 ऑफ 2001 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर की गई शिकायत के संदर्भ में पारित किया गया था, पुष्टि की गई है।

3. अपीलार्थी का विवाह 22 जून, 1989 को प्रत्यर्थी नं. 2 के साथ संपन्न हुआ था। इस विवाह के बाद, प्रत्यर्थी नं. 2 ने अपीलार्थी के साथ उसके ससुराल में रहना शुरू कर दिया.विवाह के अस्तित्व के दौरान, प्रत्यर्थी नं. 2 ने दो बेटियों को जन्म दिया.यह प्रत्यर्थी नं. 2 का मामला है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने अपर्याप्त दहेज लाने के लिए और उसकी भाभी आशा देवी के साथ अपीलार्थी के अवैध संबंधों पर आपत्ति जताने के लिए उसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता के अधीन करना शुरू कर दिया.प्रत्यर्थी नं. 2 का मामला है कि न केवल उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा, बल्कि अधिक दहेज प्राप्त करने के लिए उससे पैसे वसूले गए और उसे मारने का प्रयास किया गया और कई मांगों के बावजूद उसकी स्त्रीधन उसे वापस नहीं की गई.इन परिस्थितियों में, उसने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पूर्णिया की अदालत में 2001 का शिकायत मामला संख्या 1098 दायर किया और अपराध करने के लिए अपीलकर्ता और अन्य को भारतीय दंड संहिता

की धारा 498ए, 384,307 और 406 के तहत दंडनीय है अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए प्रार्थना की।

4. विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 2 को शपथ पर जांचाविद्वत मजिस्ट्रेट ने इसके बाद प्रत्यर्थी नं. 2 को जांच के लिए अन्य गवाहों को पेश करने के लिए बुलाया.इसलिए, भगेश्वर प्रसाद यादव, जो प्रत्यर्थी नं. 2 के पिता हैं, की साक्षी नं. 1 के रूप में परीक्षा की गई, बीरेंद्र कुमार, एक स्वतंत्रता व्यक्ति, की साक्षी नं. 2 के रूप में परीक्षा की गई और रामानुज कुमार, जो प्रत्यर्थी नं. 2 के चचेरे भाई हैं, की साक्षी नं. 3 के रूप में परीक्षा की गई.विद्वत मजिस्ट्रेट ने गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का अवलोकन किया और उनकी राय थी कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध का प्रथम दृष्टया गठन किया गया था.इसलिए, उन्होंने कथित अपराध का संज्ञान लिया और अपीलार्थी सहित आरोपी के खिलाफ समन जारी किया.सम्मन प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता और अन्य ने इसे रद्द करने के लिए विद्वत सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया की अदालत में 2002 का आपराधिक संशोधन संख्या 233 दायर किया.इसलिए, मामले का रिकॉर्ड सत्र न्यायालय द्वारा विद्वत मजिस्ट्रेट के न्यायालय से मांगा गया था।

5. 19 अक्टूबर, 2002 को अपीलार्थी ने पूर्णिया के विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया एवं जमानत के लिए आवेदन किया। चूंकि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं था क्योंकि उसे सत्र न्यायालय द्वारा समन किया गया था, इसलिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्णिया के जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से मूल अभिलेख मांगने का आदेश पारित किया। यद्यपि जमानत के लिए आवेदन की प्रति मूल शिकायतकर्ता के विद्वत अधिवक्ता पर तामील की गई थी, विद्वत मजिस्ट्रेट ने सेशन न्यायालय से मामले के समन अभिलेख को जारी करने के आदेश में यह संकेत नहीं दिया था कि अपीलार्थी की सुनवाई उसी दिन की जाएगी। 2001 का शिकायत मामला

संख्या 1098 का मूल मामला रिकॉर्ड उसी दिन यानी 19 अक्टूबर, 2002 को विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में प्राप्त हुआ था। विद्वत मजिस्ट्रेट ने उसी दिन सुनवाई के लिए जमानत आवेदन स्वीकार किया। विद्वत मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2002 में प्रत्यर्थी नं. 2 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर तलाक की याचिका के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों को भी ध्यान में रखा और प्रत्यर्थी नं. 2 या उसके विद्वत वकील को सुने बिना, जमानत पर अपीलार्थी का विस्तार किया.

6. इसके बाद, प्रत्यर्थी नं. 2 ने जमानत रद्द करने के लिए विद्वत जिला और सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया के न्यायालय में 2003 की आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 13 में कार्यवाही की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। यह उसके द्वारा देखा गया कि जमानत आवेदन अपीलार्थी द्वारा उसी दिन प्रस्तुत किया गया था जिस दिन उसने विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.यह भी कहा गया कि यह जानने के बाद कि अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा समन जारी करने को रद्द करने के लिए दायर 2002 के आपराधिक संशोधन संख्या 233 के संबंध में मूल रिकॉर्ड सेशन कोर्ट, पूर्णिया में पड़ा था, विद्वत मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट से मामले का रिकॉर्ड मांगते हुए एक आदेश पारित किया था.यह भी देखा गया कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के विद्वत वकील को नहीं सुना और उसके द्वारा जमानत आवेदन की सुनवाई तय करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया, लेकिन उसी दिन जमानत मंजूर की गई.विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा यह नोट किया गया कि यद्यपि शिकायत प्रत्यर्थी नं. 2 द्वारा 1 अक्टूबर, 2002, को दाखिल की गई थी, विद्वत मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2000, में अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही को ध्यान में रखा था, अर्थात्, अपराध का संज्ञान लेने के बाद अन्य दस्तावेजों पर भरोसा भी किया था मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वत सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने न्यायिक के अलावा अन्य विचारों पर जमानत

पर अपीलार्थी को बढ़ा दिया था इसलिए, विद्वत सत्र न्यायाधीश ने, 8 जनवरी, 2004, दिनांकित आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी नं. २ द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार किया और अपीलार्थी को दी गई जमानत रद्द कर दी.

7. व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता पटना के उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2004 का 2790 दाखिल किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को 2 मई, 2007 के निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया है, जिसने तत्काल अपील को जन्म दिया है।

8. इस न्यायालय ने पक्षकार के विद्वत वकील के लिए सुनवाई की है और अपील के भाग के रूप में दस्तावेजों को ध्यान में रखा.

9. अपीलार्थी के विद्वत वकील ने तर्क दिया कि जमानत का रद्दकरण केवल जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के पश्चात् के आचरण और पर्यवेक्षण करने वाली परिस्थितियों के संदर्भ में हो सकता है। उनके अनुसार रद्द करने का आवेदन जमानत मंजूर करने से पहले जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में विचारणीय नहीं होगा। उन्होंने *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी* [(2005) 8 एस. सी. सी. 21] वाले मामले में निम्नलिखित संप्रेक्षणों पर भरोसा किया एवं उक्त विवाद के समर्थन मेंः

> "*दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य* [1995 (1) एससीसी 349] और *समरेन्द्रनाथ भट्टाचार्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* [2004 (11) एससीसी 165] के मामले में जमानत रद्द करने के लिए आवेदनों से संबंधित है न कि जमानत मंजूर करने के आदेशों के खिलाफ अपील से। रद्द करने के लिए एक आवेदन में, जमानत पर रिहा होने के बाद और केवल पर्यवेक्षण करने वाली परिस्थितियां प्रासंगिक हैं। लेकिन जमानत की मंजूरी के खिलाफ एक अपील में, धारा 439 के साथ पठित धारा 437 के तहत प्रासंगिक सभी पहलू, प्रासंगिक होंगे। तथापि, हम सहमत हैं कि जमानत की

मंजूरी के विरुद्ध अपीलों पर, जहां अभियुक्त काफी समय से फरार है, विचार करते समय और विनिश्चय करते समय जमानत के पश्चात् के आचरण और पर्यवेक्षण करने वाली परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। किंतु जमानत के रद्दकरण के लिए आवेदनों के मामले में विचार किए जाने के लिए केवल यही कारक नहीं हैं। ”

(जोर दिया गया)

उक्त संप्रेक्षणों के सावधानीपूर्वक पठन से पता चलता है कि पहले से ही मंजूर जमानत पर विचार करने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए और जमानत की नामंजूर करने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इंगित किया कि जमानत को रद्द करने के लिए, जमानत पर रिहा होने के बाद का आचरण और परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करना प्रासंगिक होगा। उक्त मताभिव्यक्तियों का आशय अन्य आधारों पर समुचित मामलों में जमानत रद्द करने की वरिष्ठ न्यायालय की शक्ति को निर्बंधित करना नहीं था। वास्तव में अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि एक वरिष्ठ न्यायालय यह पाता है कि जमानत मंजूर करने वाले न्यायालय ने अप्रासंगिक सामग्री पर कार्य किया था या यदि विचार का उपयोग नहीं किया था या जमानत मंजूर करने के लिए किसी कानूनी प्रतिबंध पर ध्यान देने में विफलता थी, या क्या स्पष्ट था उदाहरण के लिए, जहां आवश्यक हो लोक अभियोजक/शिकायतकर्ता की सुनवाई करने में असफलता, वास्तव में जमानत रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है। (देखें *गजानंद अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य* [2006 (9) स्केल 378] और *रिजवान अकबर हुसैन सैयद बनाम महमूद हुसैन* [2007 (10) एस. सी. 368]।

10. इसके अलावा, जमानत रद्द करते समय, वरिष्ठ न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करना न्यायोचित होगा कि क्या जमानत मंजूर करने वाले न्यायालय द्वारा अप्रासंगिक सामग्री पर विचार किया गया था।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी स्वयं और अन्य लोगों ने विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को अभिखंडित करने के लिए पुनरीक्षण दाखिल करने के रूप में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसलिए विद्वत सत्र न्यायाधीश ने विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत से अभिलेख मंगाया था.19 अक्टूबर, 2002 को, अपीलार्थी ने अचानक विद्वत न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम क्षेणी, पूर्णिया के समक्ष आत्मसमर्पण करने का फैसला किया था एवं एक जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विद्वत मजिस्ट्रेट ने पाया कि मामले का रिकॉर्ड सत्र न्यायालय में संशोधन के संदर्भ में पड़ा था, जो अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया था.विद्वत मजिस्ट्रेट ने प्रतीक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा और एक प्रवर न्यायालय में लंबित रिकॉर्ड के लिए बुलाए गए न्यायिक आदेश को पारित किया। विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित न्यायिक आदेश को ध्यान में रखते हुए, सत्र न्यायालय की रजिस्ट्री ने मामले का रिकॉर्ड तुरंत विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत को भेज दिया। इसके बाद विद्वत मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई की। रिकॉर्ड को समन करने के आदेश में, विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उसी दिन, अर्थात्, 19 अक्टूबर, 2002 को सुनवाई की जाएगी.शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को बिल्कुल भी नोटिस पर नहीं रखा गया था और इसलिए, जब जमानत की सुनवाई की गई तो वह उस समय उपस्थित नहीं रह सकता था। विद्वत मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया.यह स्वीकार किया जाता है कि ये दस्तावेज संज्ञान लेने के समय के बाद के थे। उन दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने जमानत पर अपीलार्थी का विस्तार किया। विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्शित अनावश्यक जल्दबाजी और शिकायतकर्ता के विद्वत वकील को सुने बिना उसी दिन जमानत आवेदन पर सुनवाई करने के उनके निर्णय ने विद्वत सत्र न्यायाधीश को विद्वत मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर किया.तथ्यों पर और

मामले की परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि विद्वत सेशन न्यायाधीश विद्वत मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में न्यायोचित था और यह अभिनिर्धारित करता है कि जमानत मंजूर करने वाला आदेश विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक के अलावा अन्य विचारों के लिए पारित किया गया था.तथ्य के इस निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में पुष्टि की गई हैः-

> "दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना। शिकायत याचिका के साथ-साथ दोनों अदालतों के आदेश का भी अध्ययन किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की जमानत बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में दी गई थी.पूरा कार्यालय और पीठासीन अधिकारी इतनी जल्दबाजी में था कि सेशन न्यायालय से रिकॉर्ड मंगाए जाने सहित सभी औपचारिकताएं उसी दिन पूरी कर ली गईं और जमानत मंजूर करने का आदेश भी उसी दिन शिकायतकर्ता के वकील के अनुपस्थिति में पारित कर दिया गया। विद्वत निचली अदालत का आदेश, जो इतने सारे पृष्ठों में चलता है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पीठासीन अधिकारी याचिकाकर्ता को जमानत देने में कितना इच्छुक था जो विरोधी पक्ष सं. 2 का पति हैं। "

12. विद्वान सत्रों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने धारा 437 के तहत अपने विवेक का इस्तेमाल किया था। छुपे हुए मकसद से विद्वत मजिस्ट्रेट स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को जमानत देने पर तुले हुए थे और इसलिए, उन्होंने न केवल उसी दिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करने का फैसला किया, बल्कि वरिय न्यायालय से रिकॉर्ड भी मंगाया और ने शिकायतकर्ता के विद्वत वकील को सुने बिना अपीलकर्ता को जमानत दे दी। चूंकि विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा एक मनमाने ढंग से और परोक्ष उद्देश्यों के साथ न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग किया गया था, इसलिए विद्वत सत्र न्यायालय

अपीलार्थी को जमानत देने वाले आदेश को रद्द करने में उचित था.कम से कम कहने के लिए, विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश उसे दिए गए विवेक के मनमाने प्रयोग का परिणाम था.इसके अलावा विद्वत मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से अप्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखा, जिनका शिकायत में कभी उल्लेख नहीं किया गया था.उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए विद्वत मजिस्ट्रेट ने किसी भी तरह से अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की अपनी चिंता व्यक्त की.तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि उच्च न्यायालय ने जमानत को रद्द करने वाले सत्र न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटियां नहीं की, जो विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अपीलार्थी को मनमाने ढंग से प्रदान की गई और, इसलिए, तत्काल अपील खारिज की जा सकती है।

13. पूर्वगामी कारणों से अपील विफल हो जाती है और अपास्त की जाती है।

एन.जे अपील ख़ारिज

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।